



राजस्व कोर्ट (महोदय) (अ.म.)

न्यायालय श्रीमान ~~अमर~~ महोदय, सागर (म.प्र.)

R-2195-III/114

- १- विजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
- २- सतीश कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
- ३- स्व. संजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता
- ४- हरि नारायण वल्द मुन्नालाल गुप्ता

सभी निवासी सदर बाजार, सागर तहसिल सागर == == ==  
पुनरीक्षा कर्ता आवेदकगण

बनाम

अमित केशखानी वल्द हरिओम केशखानी  
निवासी सदर बाजार, सागर तहसिल सागर == == अनावेदक

पुनरीक्षा आवेदन पत्र अन्तर्गत घाटा ५० म.प्र.मू-२००३सहित

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २२-आ.७० वर्ष २०१२-१३ नाम पदाकार अमित वल्द हरिओम बनाम विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक २२।४।१४ से दुःखी होकर यह रिक्तीजन प्रस्तुत है।

पुनरीक्षा के सिद्धांत तथ्य एवं आधार

१- यहकि, पुनरीक्षा कर्ता आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक २२।४।०१४ के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष पुनरीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक ३०।६।०१४ को दौत्राधिकार के अभाव मे निरस्त किया है, जिसके उपरान्त माननीय के समक्ष यह पुनरीक्षा प्रस्तुत किया है।

२- यहकि, अमित केशखानी वल्द हरिओम केशखानी निवासी

11/11/2014/817114  
श्री- वृत्त न्यायालय  
H. Shri. Small Court  
सागर  
11/11/14  
मैजिस्ट्रेट

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R- 2195-III/2014 जिला सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-15 सागर कैंप	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अमित चौकसे उपर । उन्हे ग्राह्यता पर सुना । प्रकरण ग्राह्यता पर आदेशार्थी ।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	
4-2-15 सागर कैंप	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार तहसील जिला सागर के प्र. क्र. 22/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-4-14 की सत्यप्रतिलिपि का व अभिलेख का मंगलोलोकन किया गया, जिससे दुरिखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक श्री अमित केशरवानी का नाम दर्ज है। यदि इससे आवेदक असंतुष्ट है तो उसे गलत सिद्ध करने का भार भी उन्हीं का है तथा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का का अवसर तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में आवेदक के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्रग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	